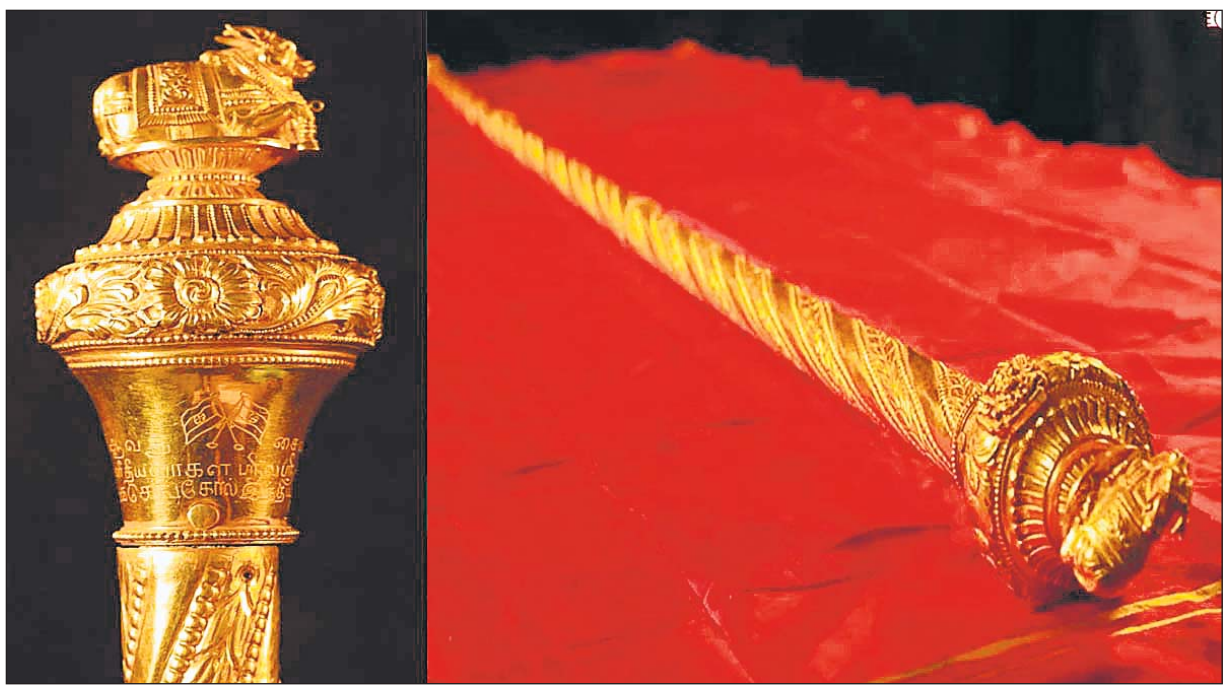

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ब्रिटिश शासन से 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की परम्परा को दोहराते हुये इस महत्वपूर्ण दिन के ऐतिहासिक एवं पवित्र प्रतीक "सेंगोल" अर्थात् राजदण्ड को स्वीकार करेंगे। नये संसद भवन के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक परम्परा को एक बार फिर दोहरायेंगे। ऐतिहासिक "सेंगोल" को बाद में लोकसभाध्यक्ष के शासन के निकट स्थापित किया जायेगा। उस समय इस महान भारतीय परम्परा का निर्वाह करने के लिए ब्रिटिश वाइसरॉय खुद भारत आये थे और उन्होंने 14 अगस्त 1947 को यह पवित्र प्रतीक प्र.मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु को सौंपा था।

ऐतिहासिक "सेंगोल" (राजदण्ड) को नये संसद भवन में स्थापित करेंगे प्र.मंत्री मोदी

14 अगस्त 1947 के दिन सत्ता हस्तांतरण करते समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरु को ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउन्टबेटन ने यह राजदण्ड सौंपा था

- **पंडित नेहरू ने अपने आवास पर लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अधिनम से आये धार्मिक शिष्टमंडल से सेंगोल को स्वीकार किया था।**
- **गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि, सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेमई शब्द से बना है जिसका अर्थ नीति परायणता है। उन्होंने कहा कि, सेंगोल न्याय और नीति पर आधारित शासन के भाव से जुड़ा है।**

नई दिल्ली, 24 मई। नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, 14 अगस्त 1947 की सत्ता हस्तांतरण की परम्परा को दोहराते हुए पवित्र "सेंगोल" (राजदण्ड) को स्वीकार करेंगे, जिसे बाद में लोकसभाध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनेक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के समय प्राचीन भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पवित्र "सेंगोल" को स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा कि, ब्रिटिश सरकार ने इस विशेष अवसर और परंपरा के लिए वाइसरॉय लॉर्ड माउन्टबैटन को भारत भेजा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपने आवास पर लॉर्ड माउन्टबैटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अधिनम से आये धार्मिक शिष्टमंडल से सेंगोल को स्वीकार किया था।

शाह ने कहा कि सेंगोल भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा है और इसका संबंध आठवीं सदी के चोल साम्राज्य से है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेमई शब्द से बना है जिसका अर्थ नीति परायणता है। उन्होंने कहा कि, सेंगोल न्याय और नीति पर आधारित शासन के भाव से जुड़ा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आगामी रविवार को जब प्रधानमंत्री नये संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो तमिलनाडु के 20 अधिनम के अध्यक्ष मोदी को यह सेंगोल प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह पवित्र सेंगोल न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का प्रतीक है इसलिए इसकी जगह संग्रहालय के बजाय संसद भवन होनी चाहिए।

शाह ने बताया कि, यह सेंगोल अब तक इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा था। शाह ने 75 वर्ष पुरानी इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सत्ता हस्तांतरण से पहले लॉर्ड माउन्टबैटन ने पंडित नेहरू से इस मौके पर किये जाने वाले विशेष समारोह के बारे में पूछा तो पंडित नेहरू ने भारत रत्न और महान स्वतंत्रता सेनानी तथा विचारक सी राजगोपालाचारी के साथ सलाह की। राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित भारत की प्राचीन परंपरा सेंगोल के बारे में बताया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पंडित नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर, पूर्ण विधि विधान से यह सेंगोल प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा देश के मीडिया ने सेंगोल के बारे में विस्तार से समाचार प्रकाशित किये थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के बाद यह सेंगोल ओझल हो गया तथा 1978 में दक्षिण के परमाचार्य ने अपने एक अनुयायी को सेंगोल के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद से यह इलाहाबाद के संग्रहालय में था। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इन सब बातों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इस बारे में विस्तार से अध्ययन तथा जांच कराने के बाद इस परंपरा को दोबारा जीवंत करने का निर्णय लिया।

शाह ने इस मौके पर सेंगोल से संबंधित एक वेबसाइट भी शुरू की जिस पर सेंगोल से संबंधित सभी जानकारी विस्तार से उपलब्ध है।

'पानी की टंकी' वाली वन भूमि का सर्वे करेगी हाई कोर्ट द्वारा गठित पांच सदस्यों की कमेटी

न्यायालय के आदेश पर बनी यह कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को सौंपेगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 24 मई। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर जलदाय विभाग द्वारा अवैध तरीके से वॉटर टैंक बनाने का मामला तूल पकड़ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में मनोज जांगिड़ द्वारा जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दायर की गई थी, मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर इस भूमि का टाइटल जांचने के लिए पांच सदस्यों की संयुक्त जांच कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जलदाय, राजस्व, वक्फ बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी और पी.आई.एल. दायर करने वाले मनोज जांगिड़ अथवा उनके प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। यह जांच समिति विवादित भूमि का संयुक्त सर्वे करके अगले 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को सौंपेगी।

- **इस कमेटी में जलदाय, राजस्व, वक्फ बोर्ड, वन विभाग और पी.आई.एल. दायर करने वाले प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।**

कलेक्टर द्वारा 23 मई को आदेश जारी कर गठित की गई इस कमेटी में उप वन संरक्षक जयपुर, जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता, तहसीलदार जयपुर, वक्फ बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और पी.आई.एल. दायर करने वाले मनोज जांगिड़ अथवा उनके प्रतिनिधि को जोड़ा गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि, उपवन संरक्षक जयपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि, वनखंड़ बड़ी लाइन आमेर-54 की भूमि 21 नवंबर 1961 को विज्ञप्ति जारी कर आरक्षित वन घोषित किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 2 मार्च 1972 को इस वनखंड भूमि में से कुछ खसरों की भूमि को नगर विकास न्याय को स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन वन विभाग के पास उक्त भूमि का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जलदाय विभाग द्वारा जिस भूमि पर पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, वह वन भूमि है। ऐसे में इन पांच सदस्यों की जांच समिति उक्त भूमि का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

ज्ञात रहे कि गत 19 मई को राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने मनोज कुमार ने वन विभाग, जलदाय विभाग तथा वक्फ बोर्ड के अफसरों व प्रतिनिधियों को निर्देश दिया था कि, अगली तारीख तक इस भूमि के सही निर्धारण के साथ बनाए गए नक्शे समेत जवाब अदालत में पेश करें। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 30 मई तय की है।

अडानी ग्रुप की वियतनाम में 3 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना

नई दिल्ली, 24 मई। उद्योगपति गौतम अडानी समूह वियतनाम में पोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 3 बिलियन डॉलर तक निवेश करने की संभावना तलाश रहा है। वियतनाम सरकार ने एक बयान में यह जानकारी दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अडानी पोर्ट्स के सीईओ करण अडानी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भी अडानी समूह के निवेश के संकेत दिए।

इस मुलाकात के बाद करण अडानी ने कहा कि भारत की बड़ी कंपनियों के लिए यह देश अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने को तैयार है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने अडानी समूह का देश में स्वागत किया है। ऐसा माना जा रहा है कि वियतनाम में अडानी समूह लंबी अवधि में 10 बिलियन तक निवेश कर सकता है।

इस बीच, बुधवार को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.13 प्रतिशत तक गिर गया। ग्रुप की सात कंपनियों के शेयर बुधवार को नुकसान में बंद हुए।

कैलाश सत्यार्थी ने 41 बाल मजदूर मुक्त कराये

ये बच्चे आजाद मार्केट (दिल्ली) की फैक्टरियों में पिछले काफी समय से बाल मजदूरी कर रहे थे

- **पिछले हफ्ते बीबीए, दिल्ली कैंट के एसडीएम, श्रम विभाग और पुलिस की साझा कार्रवाई में नारायणा से 14 बच्चों को मुक्त कराया गया था। इसमें ज्यादातर की सेहत खराब थी**

नयी दिल्ली, 24 मई (वार्ता)। देश में बच्चों के हित और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली नोबल पुरूस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) के प्रयासों और पुलिस की मदद से राजधानी दिल्ली के आजाद मार्केट में कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले 41 बाल मजदूरों को आजाद कराया गया है।

बच्चों के दुर्व्यापार और बाल मजदूरी की खतरनाक समस्या पर बीबीए के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा, यह पूरे समाज के लिए चिंता की बात है कि आजादी के दशकों बाद भी हम अपने बच्चों को बाल मजदूरी के कोढ़ से मुक्त नहीं करा पाए हैं। खिलौनों से खेलने की उम्र में बच्चों को खिलौना बनाते हुए देखना हम सभी को शर्मसार करने वाली बात है।

इस कार्रवाई के बाद आजाद मार्केट के राम बाग रोड पर स्थित दर्जन भर फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और इनके मालिकों के खिलाफ बाड़ा हिंदू राव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। छुड़ाए गए बच्चे बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के हैं।

छुड़ाए जाने के बाद मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी (मध्य दिल्ली) ने इन सभी बच्चों की चिकित्सा जांच की। इसके बाद इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें एक आश्रय गृह भेज दिया गया।

इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे कोतवाली, दरियागंज के एसडीएम अरविंद राणा ने आदेश में कहा कि इन फैक्ट्री मालिकों ने बाल एवं किशोर श्रम कानून, बाल न्याय कानून और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ बंधुआ मजदूरी कानून, बाल श्रम कानून, बाल न्याय कानून और ट्रैफिकिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की ली है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दस दिन में बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने की बीबीए की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले हफ्ते बीबीए, दिल्ली कैंट के एसडीएम, श्रम विभाग और पुलिस की साझा कार्रवाई में नारायणा से 14 बच्चों को मुक्त कराया गया था। इसमें ज्यादातर की सेहत खराब थी और उनके हाथ-पांव पर जले के निशान थे।

पार्सल नहीं पहुंचा,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवाद दायर करने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने यह आदेश नागर मल शर्मा के परिवाद पर दिया। परिवाद में कहा गया कि 9 मार्च 2022 को परिवादी ने उमर टेक्सटाइल्स से 9,450 रुपए की साडी खरीदी और उसे पानीपत पहुंचाने के लिए विपक्षी कार्गो के जरिए बुकिंग करवाई। कई दिनों तक पार्सल नहीं पहुंचा तो उसने कार्गो कम्पनी से बातचीत की, लेकिन कम्पनी टालमटोल करती रही। परिवादी ने पार्सल वापस मांगा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उसके साथ अभ्रदता की गई। परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए पार्सल की राशि हर्जाने सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। आयोग ने विपक्षी को नोटिस दिया, लेकिन ना तो उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसकी ओर से कोई उपस्थित हुआ, जिस पर आयोग ने दस्तावेज व साक्ष्यों पर विपक्षी कार्गो कंपनी को पार्सल की राशि लौटाने का निर्देश देते हुए उस पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

'प्रजातंत्र की आत्मा, खींच कर, संसद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का उद्घाटन स्वयं करेंगे, हमारे लोकतंत्र का न केवल घोर अपमान, बल्कि इस पर सीधा हमला है तथा (यह स्थिति) इसके अनुरुप प्रतिक्रिया की माँग करती है।"

विपक्षी दलों ने कहा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 79 में कहता है कि "संघ के लिये एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होंगे जो क्रमशः काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) तथा हाउस ऑफ द पीपुल (लोकसभा) के नाम से जाने जायेंगे।"

वक्तव्य कहता है, "राष्ट्रपति न केवल भारत के "हैड ऑफ द स्टेट" हैं, बल्कि संसद का अभिन्न अंग हैं। वे संसद को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा संबोधित करते हैं। संसद के अधिनियम के लागू होने के लिये उनकी मंजूरी जरूरी होती है। संक्षेप में, संसद का काम-काज राष्ट्रपति के बिना नहीं हो सकता। फिर भी, प्रधानमंत्री ने उनके बिना नये संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय ले लिया है। यह मर्यादाहीन कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान तथा संविधान की भावना का उल्लंघन करने वाला है। यह समावेश की भावना जिसने राष्ट्र को अपनी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का जश्न मनाते देखा था, की जड़ काटना है।"

बयान में आगे कहा गया है कि "अलोकतांत्रिक कृत्य प्रधानमंत्री के लिये नये नहीं है, जिन्होंने संसद को बड़ी निष्ठुरता के साथ खोखला कर दिया है।"

विपक्षी दलों ने कहा है कि संसद के विपक्षी सदस्यों ने जब भारत की जनता के मुद्दे उठाये तो उन्हें डिस्क्वालिफाइड, निलम्बित तथा खामोश कर दिया गया है।

इन दलों ने कहा, "सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद विधेयक, जिनमें तीन कृषि विधेयक भी शामिल हैं, तकरीबन बिना बहस के पारित कर दिये गये हैं तथा ससंदीय कमेटियाँ, व्यवहारिक स्तर पर समाप्त कर दी गई हैं। नया संसद भवन, सर्दियों में एक बार होने वाली महामारी के दौरान, बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाया गया तथा इसके लिये भारत की जनता, अर्थात् सांसदों से विचार-विमर्श तक नहीं किया गया, जिनके वास्ते यह बनवाया गया है।"

विपक्षी दलों ने यह टिप्पणी करते हुये कि संसद से लोकतंत्र की आत्मा चूस ली गई है, कहा, "इस प्रकार इस नये भवन का कोई महत्व नहीं है। हम इस स्वैच्छाचारी प्रधानमंत्री तथा उसकी सरकार के खिलाफ पूरे मन एवं दृढ़ता से लड़ते रहेंगे तथा अपना संदेश सीधे भारत की जनता तक पहुँचायेंगे।"

टी.एम.सी., आप तथा सी.पी.आई ने बहिष्कार की घोषणा मंगलवार को ही कर दी थी। चार पार्टियों- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बी.जे.डी., तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की बी.आर.एस., आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय.एस. जगमोहन रेड्डी की वाय.एस.आर.सी.पी. तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा ने शेष विपक्ष के साथ शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। ये चारों ही दल, एन.डी.ए. शासनकाल में केन्द्र सरकार को सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं। उनका यह निर्णय अपेक्षित ही था।

वक्तव्य में कहा गया है कि किस प्रकार से मोदी सरकार, 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही, सोचे-समझे तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करती आ रही है तथा उनकी जड़ें खोदती आ रही है तथा साफ तौर पर लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में विपक्ष की भूमिका को नकारती आ रही है।

उद्धव ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ठाकरे ने केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रैंस की और कहा कि हम सब देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मुझे लगता है कि हमें "विपक्षी दल" नहीं कहना चाहिए। असल में उन्हें (भाजपा) विपक्षी कहना चाहिए, क्योंकि वे लोकतंत्र संविधान के खिलाफ हैं।

हीट वेव का दौर खत्म, अगले 2-3 दिन होगी देश में झमाझम बारिश

- **इंडियन मीटिरियॉलजिकल डिपार्टमैंट (आई.एम.डी.) ने नये पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आने की भविष्यवाणी की**

नई दिल्ली, 24 मई। इंडियन मीटिरियोलजिकल डिपार्टमैंट (आई.एम.डी.) ने एक बड़ी खुशखबरी दी है और बताया कि पूरे भारत में लू का प्रकोप समाप्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली-एन.सी.आर. समेत देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पहले ही आई.एम.डी. ने पहले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 मई से 27 मई तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई थी। बिहार-राजस्थान, दक्षिणी भारत के कई इलाकों में हुई तेज आंधी के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बेंगलुरु में बारिश से तबाही भी मची है।

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया है कि पूरे भारत में आज लू का प्रकोप समाप्त हो गया है। आज से तापमान में कमी आएगी और बादल छाए रहेंगे। हमने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में भी तूफान के आसार हैं।

'हमको जे.डी.ए....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जे.डी.ए. के अधिकारियों से सवाल पूछ सकती है कि क्यों उनकी कॉलोनी के नियमन के लिए कैंप नहीं लगाया गया जबकि उनकी कॉलोनी में सभी मापदण्डों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

उन्होंने बताया कि जे.डी.ए. ने उनके जैसी कई कॉलोनियों का नियमन किया है परन्तु उनकी कॉलोनी के निवासियों को वंचित रखा है, "इसका क्या कारण है। आप जे.डी.ए. से ही पूछें, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।"

उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पृथ्वीराज नगर में बिजली चोरी इसलिए ही हो रही है क्योंकि जे.डी.ए. ने पट्टा जारी नहीं करके लोगों के समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा है।

बहस के दौरान सरकार और डिस्कॉम की तरफ से पैरवी कर रहे वकीलों की ओर इस तथ्य को भी नकारा नहीं गया कि राज्य सरकार ने पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में सभी लोगों को बिजली कनेक्शन आवंटित करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सरकार अब "इलेक्शन मोड" में है।

अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए इस मामले को सूचीबद्ध किया है।

रेल वैगन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने भी अपने रायबरेली प्लांट, जो आईआर की उत्पादन इकाई है, में पहियों का निर्माण शुरू कर दिया है। आई आर के सूत्रों ने कहा "2300 करोड़ रु0 की लागत से स्थापित इस प्लान्ट में 100,000 पहिये प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता है लेकिन उत्पादन काफी कम रहा है तथा उत्पादन लागत बहुत ज्यादा आई है क्योंकि आर आई एन एल इंजीनियर इसके उतने ज्यादा विशेषज्ञ नहीं थे। पिछले वर्षों में, आई आर की कोशिश रही कि प्राइवेट निवेशक आर आई एन एल का अधिग्रहण कर लें,लेकिन आई आर को इसमें कामयाबी नहीं मिली। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है, "जहाँ रामकृष्ण-टीटागढ़ प्लान्ट को उत्पादन शुरू करने में दो वर्ष लगेंगे, वहीं आर आई एन एल प्लान्ट की उत्पादन क्षमता पहले दिन से ही बढ़ जायेगी। सरकार, प्राइवेट निवेशकों को आकर्षित करने के लिये, सब्सिडी के रूप में "लाइबिलिटी गैप फन्डिंग" की पेशकश कर सकती थी। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं किया गया।"

ई.डी. ने सांसद संजय सिंह के दो सहयोगियों के खिलाफ छापे मारे

संजय सिंह ने छापों के संदर्भ में दावा किया कि, ई.डी. ने कोना-कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला

- **संजय सिंह ने ई.डी. के छापों को राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया और कहा कि, मेरे दोस्तों और सहयोगियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है।**

नयी दिल्ली, 24 मई (वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित दिल्ली शराब नीति मामले में उनके दो सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली।

सिंह ने ट्वीट किया, मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच का पर्दाफाश पूरे देश के सामने हुआ। ईडी ने मानी अपनी गलती जब कुछ नहीं मिला तो आज उसने ने मेरे साथियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर छापा मारा।

सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। यह अत्याचार की पराकाष्ठा है। आप कितना भी अत्याचार करें। लड़ाई जारी रहेगी।

आप नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट वीडियो संदेश में ईडी के छापे को लेकर केंद्र पर कटाक्ष किया और आरोप लगाया, सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हम ईडी के दुरुपयोग का पर्दाफाश करेंगे। लड़ाई जारी रहेगी।

आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यसभा सांसद संजय के सहयोगियों के घर ईडी की छापेमारी को बुधवार को राजनीति से प्रेरित करार दिया।

'आप' के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, पिछले करीब एक साल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद-प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में खुलकर 'आप' लोगों का नाम लेकर कहते हैं कि अब इनको गिरफ्तार करेंगे और ईडी-सीबीआई का छापा पड़ेगा। पूरी दिल्ली में भाजपा एक तय तरीके से 'आप' नेताओं के बारे में खबरें फैलाती है कि आज इससे गिरफ्तार करेंगे।

भारद्वाज ने कहा, जिस तरह संजय सिंह का पूरा प्रकरण सामने आया, अगर कोई और देश होता या फिर केंद्र सरकार में किसी और पार्टी की सरकार होती तो उसके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात थी। संजय सिंह ने जिस तरह से संसद में अडानी मामले में खुलकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, उसके बाद भाजपा वाले कहने लगे कि अब अगला नंबर संजय सिंह का लगेगा। संजय सिंह का नाम चार्जशीट के अंदर डाला गया।

संजय सिंह ने ईडी को लीगल नोटिस दिया। उस लीगल नोटिस से घबराकर ईडी का लिखित जवाब आया कि उन्होंने गलती से संजय सिंह नाम डाल दिया, जोकि बहुत हैरानी की बात है।

बैंकों में कैश की कमी

नई दिल्ली, 24 मई। देश की कुछ बैंक शाखाओं में 2,000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया बुधवार को कैश की कमी के कारण अस्थायी तौर पर रोकनी पड़ी। इससे लोगों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा। बैंकों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कुछ शाखाओं में 2,000 रुपये के नोट के बदले दिए जाने वाले कम मूल्य के नोट कम पड़ गए। हालांकि कुछ समय बाद करेंसी चेस्ट से नोट आ जाने के बाद लोगों को राहत मिल गई।

विभिन्न बैंकों के शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया कि शाखाओं में कम मूल्य के नोट की कमी से जुड़ी बड़ी शिकायतें नहीं सामने आई हैं। इसके साथ ही शाखाओं में भीड़ की भी स्थिति नहीं देखने को मिली है। केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक भवेंद्र कुमार ने कहा, "हम दिल्ली सर्किल में अपनी सभी शाखाओं को 500, 200 और 100 रुपये मूल्य के नोट लगातार पहुंचा रहे हैं ताकि 2,000 रुपये के नोट बदले जा सके।

'नैक्सा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निवेश रकम को दोगुना करने और हर सप्ताह खाते में राशि जमा करने का कहकर लोगों को झांसे में लिया। वहीं हजारों पीड़ितों से करीब 2700 करोड़ रुपए ठगने के बाद आरोपी अंडरग्राउंड हो गए और विदेश जाने की योजना बनाने लगे। लेकिन लुक आउट सर्कुलर जारी होने के चलते वे भारत के बाहर नहीं जा सके। ऐसे में वे राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में फरारी काटने लगे। आखिर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908